

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਚੰ. 514] No. 514] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2004/ज्येष्ठ 18, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2004/JYAISTHA 18, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2004

का.आ. 667(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, ''विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन करती है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए. के. सिकरी होंगे।

[फा. सं. I-11034/9/2003-आई एस. III]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2004

S.O. 667(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", consisting of Mr. Justice A. K. Sikri, a sitting Judge of the Delhi High Court.

[F. No. I-11034/9/2003-IS. III]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.

1770 GI/2004